ई-संदेश

उत्तर प्रदेश

4 जुलाई, 2018 • वर्ष 1, अंक 24

सात दिन – सात पृष्ठ

मगहर आगमन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी

- डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना से मिलेंगे ढाई लाख रोजगार
- प्रदेश को मिलेंगी 2206 नई एम्बुलेंस
- प्लास्टिक कचरे से प्रदेश में होगा सड़क निर्माण
- वाराणसी से काठमाण्डू के बीच हवाई यात्रा प्रारंभ
- प्रदेश के 68 जनपदों में बनेंगे 'गो–संरक्षण केन्द्र'
- मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में यूपी बना नंबर वन

संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

50 हजार करोड़ निवेश पॉच वर्षों में

कई जिले लाभान्वित होंगे इस कॉरीडोर से

एयरोस्पेस और रक्षा उपकरणों का प्रदेश में होगा उत्पादन

बुन्देलखण्ड मे खरीदी जाएगी 3000 हेक्टेयर भूमि

डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना से मिलेंगे ढाई लाख रोजगार

एयरोस्पेस तथा रक्षा उपकरणों के प्रदेश में उत्पादन हेतु प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए **उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018** को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इस नीति के माध्यम से डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर में अगले पॉच वर्षो में 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश तथा ढाई लाख रोजगार के नवीन अवसरों के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रस्तावित कॉरीडोर देश का सबसे बड़ा कॉरीडोर होगा और इससे उत्तर प्रदेश के कई जिले लाभान्वित होंगे।

सितम्बर तक पूरा होगा कॉरीडोर हेतु भूमि अधिग्रहण का कार्य

कॉरीडोर के लिए बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सस्ती भूमि के वृहद् पार्सल उपलब्ध हैं।, विशेष रूप से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में यूपी एक्सप्रेसवेज़ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा लगभग 3000 हेक्टेअर भूमि को चिन्हित कर क्रय किया जायेगा। सितम्बर 2018 तक भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया जायेगा।

रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयों हेतु प्रोत्साहन

निजी रक्षा तथा एयरोस्पेस पार्क के निर्माण क्षेत्र जैसे एयरोस्पेस पार्ट्स तथा परीक्षण केन्द्र, हार्डवेयर, कम्पोनेंट्स, सब–कम्पोनेंट्स, प्रौद्योगिकी नवाचार केन्द्र, हाउसिंग तथा कॉमन सुविधा केन्द्रों हेतु इन पार्कों में बुनियादी औद्योगिक ढांचा प्रदान करने की सुविधा मिलेगी।

निजी रक्षा तथा एयरोस्पेस पार्क की भूमि क्रय करने हेतु ब्याज पर 50 प्रतिशत छूट मिलेगी जबकि अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 60 प्रतिशत तथा कॉमन प्रौद्योगिकी, नर्व प्रवर्तन केन्द्र और प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु ब्याज पर 60 प्रतिशत प्रतिपूर्ति सात वर्षो के लिए प्रदान की जाएगी।

स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट

पार्क की भूमि हेतु स्टाम्प ड्यूटी में शत–प्रतिशत छूट तथा पार्क में स्थापित प्रत्येक प्रथम इकाई को 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। सरकार द्वारा रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयों की स्थापना हेतु केस–टू–केस आधार पर विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था है। ■

मगहर में बनेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भव्य संत कबीर अकादमी

दुनिया के टॉप ट्रेंड में छाया #PMInMaghar हैशटैग

- **हैशटैग के ट्वीट्स की रीच 25 करोड़ और इम्प्रेशंस 40 करोड़ से अधिक**
- **हैशटैग को मिले 15 लाख रीट्वीट और 6 लाख लाइक्स**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मगहर आगमन पर सोशल मीडिया में ट्विटर पर #PMInMaghar हैशटैग कई घंटे तक ना सिर्फ भारत में टॉप ट्रेंड पर रहा बल्कि दुनिया के टॉप ट्रेंड में छा गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस हैशटैग के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन किया।

#PMInMaghar हैशटैग पर लगभग 78000 ट्वीट्स हो चुके थे जिनकी रीच 25 करोड़ और इम्प्रेशंस 40 करोड़ से भी ज्यादा रहे। इस हैशटैग से चले अभियान को करीब 15 लाख रीट्वीट मिले और 6 लाख लाइक्स। मगहर में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का लाइव प्रसारण प्रदेश सरकार के आधिकारिक यूट्यूब चैनल के साथ साथ मुख्यमंत्री कार्यालय के फेसबुक पेज व ट्विटर हैंडल पर भी किया गया। लाइव स्ट्रीमिंग की रीच भी करीब 50 लाख रही।

संत कबीर की साधना मानने से नहीं, जानने से होती है। संत कबीर मस्तमौला, फक्कड़ और अपने कर्म से वन्दनीय थे। वे धूल से उठे और माथे का चंदन बन गये। कबीर विचार बनकर आए और व्यवहार बनकर अमर हो गये। यह उद्गार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जनपद संत कबीर नगर के मगहर में संत कबीर अकादमी के शिलान्यास अवसर पर व्यक्त किए।

3 एकड़ में विकसित होगी अकादमी

यह अकादमी 24 करोड़ रुपए की लागत से तीन एकड़ के विस्तृत क्षेत्रफल में बनायी जाएगी। स्वदेश दर्शन योजना के तहत इस अकादमी का विकास किया जाएगा और इसे अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित किया जाएगा। अकादमी में संत कबीर के जीवन और दर्शन पर शोध, सर्वेक्षण, प्रकाशन और प्रदर्शन का कार्य होगा।

पुस्तकालय एवं संग्रहालय की भी होगी स्थापना

इस अकादमी में संत कबीर के साहित्य, पाण्डुलिपि, ग्रन्थ आदि का संग्रह किया जाएगा तथा ललित कला की सभी विधाओं का संचालन किया जाएगा। इसमें एक पुस्तकालय एवं संग्रहालय की स्थापना होगी साथ ही, आंचलिक भाषाओं एवं लोक विधाओं का विकास भी किया जाएगा।

स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत 24 करोड़ रूपये से होगा अकादमी का विकास

कबीर के दर्शन को वैश्विक स्वरूप प्रदान करने की पहल

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि संत कबीरदास जी ने रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज उठायी। बनारस से मगहर आकर उन्होंने इस भ्रम को तोड़ा था कि मगहर में मरने से नर्क मिलता है। प्रधानमंत्री जी ने देश की प्राचीन विरासत योग को विश्व में मान्यता दिलायी है।

कबीर के दर्शन को वैश्विक स्वरूप प्रदान करने की पहल भी प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार राम, कृष्ण एवं बौद्ध सर्किट, प्रासाद तथा स्वदेश दर्शन योजनाओं के माध्यम से आध्यात्मिक महत्व के स्थानों का विकास कर रही है।

प्रधानमंत्री जी के सान्निध्य एवं मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार राज्य को विकास की नई ऊँचाइयों की ओर ले जा रही है।

आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अनुदान का पैसा सीधे खाते में भेजना (डी.बी.टी.) तथा आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से लोगों के जीवन में सुधार आया है। ■

38 जनपदों में इंसेफेलाइटिस वैक्सिनेशन अभियान

स्वच्छता और शुद्ध पेयजल से जे.ई. तथा ए.ई.एस. जैसी बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि गंदगी ही बीमारियों की जननी होती है। स्वास्थ्य के प्रति स्वच्छता को अपनाना होगा। वैक्सीन से जे.ई. को रोका जा सकता है लेकिन ए.ई.एस. जलजनित बीमारी है और इसे शुद्ध पेयजल के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस के मरीजों के लिए आयोजित नि:शुल्क चिकित्सा कैम्प में ग्राम प्रधानों का आह्वान किया कि वे इस बीमारी के लक्षण/बचाव के विषय में लोगों को जागरूक करें तथा क्या करें क्या न करें के सम्बन्ध में जन–जन को अवगत करायें।

बीमारी के नि:शुल्क इलाज की है व्यवस्था

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बीमारी के लक्षण दिखते ही तुरन्त नज़दीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर मरीज़ को ले जायें, जितना शीघ्र उपचार शुरू हो जायेगा उतनी ही जल्दी बीमारी नियंत्रित होगी। प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों एवं सी.एच.सी. तथा पी.एच.सी. पर इस बीमारी का नि:शुल्क इलाज किये जाने की व्यवस्था है।

2 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2018 तक जेई से प्रभावित 38 जनपदों में 34 लाख बच्चों को इंसेफेलाइटिस की वैक्सीन देने का अभियान चलाया गया। अब 2 से 30 जुलाई, 2018 तक 38 जनपदों में अभियान चलाया जायेगा। इस अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। किसी भी कार्यक्रम की शत–प्रतिशत सफलता में जन सहयोग आवश्यक है। अभियान में सफलता के लिए सकारात्मक रवैया अपनाकर इस बीमारी की जड़ पर प्रहार करके इस बीमारी को समाप्त किया जा सकेगा।

प्रदेश को मिलेंगी 2206 नई एम्बुलेंस

18 ब्लड कलेक्शन तथा ट्रान्सपोर्टेशन वैन भी मिलेंगी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रेषित वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2018–19 के क्रम में भारत सरकार द्वारा रू0 10,000 करोड़ की स्वीकृति इस वर्ष प्रदान की गयी है। भारत सरकार से प्राप्त अनुमति के सापेक्ष 20 प्रतिशत धनराशि संविदा मानव संसाधन हेतु, 15 प्रतिशत इन्फ्रास्ट्रक्चर, 12 प्रतिशत कम्युनिटी कार्यो तथा 13 प्रतिशत सर्विस डिलिवरी मदों में प्राप्त हुयी है।

प्रदेश के दूर–दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सेवाएं टेली–मेडिसिन के माध्यम से प्रदान किये जाने, 25 नवीन एम.सी.एच.विंग पी.पी.पी. मोड में चलाये जाने तथा प्रदेश के 100 जिला चिकित्सालयों में ई–हास्पिटल परियोजना का द्वितीय चरण में विस्तार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त 1544 नग नवीन 102–एम्बूलेन्स तथा 662 नग 108–एम्बूलेन्स क्रय किये जाने हेतु सहमति दी गयी है।

जनमानस को रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु 18 ब्लड कलेक्शन एवं ट्रान्सपोर्टेशन वैन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रदेश के 17 बडे जिला स्तरीय चिकित्सालयों में महत्वपूर्ण 8 विशेषज्ञ सेवाएं जनता को उपलब्ध हो सकें, इस दृष्टि से उक्त चिकित्सालयों के सुदृढीकरण हेतु व्यवस्था की गयी है।

निर्मल सुन्दर वाराणसी–सीएम का संकल्प

वाराणसी केवल एक नगर ही नहीं वरन् अपने आप में पूरी सांस्कृतिक विरासत है और इस विरासत को निर्मल और पवित्र रखना हम सबका दायित्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वाराणसी को स्वच्छ और दर्शनीय बनाने हेतु हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं।

गंगा घाटों पर प्रतिदिन होगी सफाई

मुख्यमंत्री जी ने वाराणसी में संचालित विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान हर हालत में स्वच्छता सुनिश्चित कराए जाने पर जोर देते हुए सफाई एवं कूड़े की उठान हेतु युद्धस्तर पर अभियान चलाये जाने के निर्देश दिए।

अब वाराणसी में किसी भी पार्क अथवा सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा जमा नहीं होगा। गंगा घाटों पर रोजाना सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी जिससे यहां आने वाले लोगों को शहर के साफ होने का एहसास होगा।

चुस्त–दुरूस्त होगी सीवरेज व पेयजल व्यवस्था

वाराणसी में सफाई, सीवरेज एवं पेयजल व्यवस्था चुस्त–दुरुस्त की जाएगी और इसके लिए लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। इन कार्यो की निरन्तर मॉनीटरिंग की जाएगी।

शहर की सभी स्ट्रीट लाइट को कार्यशील रखने के साथ–साथ 10 हजार नई स्ट्रीट लाइटें शीघ्र लगवाई जाएंगी। सभी सड़कों की मरम्मत के साथ–साथ उन्हें गड्ढामुक्त किया जायेगा।सड़कों पर लगे अनावश्यक विद्युत खम्भों को हटवाया जाएगा तथा वाराणसी की थीम पर जगह–जगह वॉल पेटिंग आदि कराकर शहर को संवारा जाएगा।

गोइठहा में निर्मित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की 142 किमी. लम्बी लाइन के डीसिल्टिंग कार्य में श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर इस कार्य को शीघ्र पूरा कराया जायेगा। गौरतलब है कि दीनापुर एवं रमना सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट के निर्माण कार्य को त्वरित गति से पूर्ण किया जा रहा है।

प्रतिभाओं के प्रोत्साहन हेतु सदैव तत्पर है प्रदेश सरकार

मुख्यमंत्री जी ने पीलीभीत की मेधावी बहनों कु. हनी सिंह और कु. हँसी सिंह को दी 51–51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद पीलीभीत के बीसलपुर की निवासी दो मेधावी बहनों 12 वर्षीया कु. हनी सिंह एवं 9 वर्षीया कु. हँसी सिंह को 51–51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दोनों बहनें प्रदेश की विलक्षण प्रतिभाएं हैं। राज्य सरकार ऐसी प्रतिभाओं के प्रोत्साहन हेतु हर सम्भव सहयोग हेतु तत्पर है। भविष्य में यह प्रतिभाएं अवश्य ही देश और प्रदेश का नाम रौशन करेंगी। कु. हनी सिंह एवं कु. हँसी सिंह को सामान्य ज्ञान में विशेष महारत हासिल है। साथ ही, **'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'** तथा **स्वच्छता अभियान** आदि से भी दोनों बहनें जुड़ी हुई हैं।

महिला समूहों के माध्यम से दुग्ध क्रान्ति की नई पहल

बुन्देलखण्ड की समृद्धि एवं महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु डेयरी परियोजना

बुन्देलखण्ड की महिलाओं को सशक्त एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी परियोजना संचालित की जायेगी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इसके लिए सर्वप्रथम 5 जनपदों–बांदा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट एवं झांसी के 600 गांवों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया जायगे।।

इस डेयरी परियोजना पर आगमी तीन वर्षो तक 43.58 करोड़ की धनराशि व्यय की जायेगी। जिसमें 26.15 करोड़ भारत सरकार तथा 17.43 करोड़ रुपये राज्य सरकार व्यय करेगी।

यह परियोजना बुन्देलखण्ड में गठित महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए दुग्ध क्रान्ति की नयी पहल साबित होगी। सही मायने में कहा जाय तो यह परियोजना बुन्देलखण्ड की आर्थिक समृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार की ओर से एक तोहफा है।

ग्रामीण आजीविका मिशन की इस डेयरी परियोजना हेतु पांच जनपदों के 37 विकास खण्डों के 1146 ग्राम पंचायतों के 1340 गांवों में कुल 11650 स्वयं सहायता समूहों का गठन करते हुए 128150 ग्रामीण क्षेत्र की गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में जोड़ा जा चुका है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 7 जनपदों में प्रतिदिन लगभग 43 लाख लीटर दूध का उत्पादन होता है, जिसमें से मात्र 7930 लीटर का विपणन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा और शेष असंगठित क्षेत्र में विपणन किया जाता है।

इसके अन्तर्गत आगामी तीन वर्षो में पांच जनपदों के 600 गांवों में 3600 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को दुग्ध उत्पादक कम्पनी से जोड़ा जायेगा। इसके अन्तर्गत पहले साल 5000 सदस्यों को दुग्ध उत्पादक कम्पनी से जोड़ा जायेगा एवं पांच वर्ष तक 48000 समूह सदस्यों को दुग्ध उत्पादक कम्पनी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

बुन्देलखण्ड कुछ मामलों में पिछड़ा हुआ है। वर्तमान सरकार के लगभग सवा साल के कार्यकाल के दौरान केन्द्र तथा राज्य सरकार के सहयोग से कई बड़ी परियोजनाएं संचालित कर बुन्देलखण्ड को तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर करने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी पहली मण्डलीय समीक्षा बैठक झांसी आयोजित कर बुन्देलखण्ड के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया था और इस दिशा में पेयजल से लेकर आर्थिक समृद्धि से संबंधित विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

राज्य सरकार बुन्देलखण्ड को आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार के साथ ही यहां के निवासियों को विकास से जोड़ना चाहती है। इसीलिए डिफेन्स कारिडोर की स्थापना को प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही बुन्देलखण्ड को दिल्ली से जोड़ने के लिए बुन्देखण्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की भी घोषणा की गई है। यह दोनों परियोजनाएं विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगी। राज्य सरकार ने पेयजल के संकट से जूझ रहे इस क्षेत्र की इस समस्या का लगभग समाधान कर दिया है।

प्लास्टिक कचरे से प्रदेश में होगा सड़क निर्माण

प्रदेश सरकार पर्यावरण के लिये खतरा बन चुके प्लास्टिक का उपयोग कर सड़क बनायेगी। लोक निर्माण विभाग अब नैनो टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक कचरा, जूट जियो टैक्सटाइल्स, प्लाई ऐश और सी.सी. का उपयोग कर नयी तकनीक से सड़क बनायेगा। इस नयी तकनीक से सड़के कम लागत में बनेंगी तथा अधिक टिकाऊ भी होंगी।

प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क पानी कम सोखेगी। आज प्लास्टिक कचरा तकनीक पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है। इस तकनीक में गिट्टी के साथ प्लास्टिक चूरा मिलाया जाता है, इससे सड़क में प्लास्टिक की एक लेयर बन जाती है जो पानी को सड़क पर रूकने नहीं देती है और पानी नहीं सोखने के कारण ये सड़क जल्दी नहीं टूटती। उन्होने बताया कि प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में भी इस तकनीक का प्रयोग हो रहा है।

विभाग प्लास्टिक का उपयोग मार्ग निर्माण में करने के लिये केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के साथ जनपद बाराबंकी में कोठी–हैदरगढ़ मार्ग (अन्य जिला मार्ग) पर कार्य करेगा। शीघ्र ही अन्य मार्गो को इस दायरे में लाया जायेगा क्योंकि प्रदेश सरकार उच्च कोटि की टिकाऊ सड़कें प्रदेश की जनता को उपलब्ध कराने के लिये कटिबद्ध है।

वाराणसी से काठमाण्डू के बीच हवाई यात्रा प्रारंभ

प्रदेश सरकार आमजन को सस्ती दरों पर हवाई यात्रा उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है और अधिक से अधिक स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वाराणसी स्थित लालबहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से काठमाण्डू (नेपाल) के बीच हवाई यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने बुद्धा एयर के विमान को हरी झण्डी दिखाकर काठमाण्डू के लिए रवाना किया। इस सेवा के प्रारंभ होने से भारत तथा नेपाल के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और पर्यटकों को नेपाल यात्रा हेतु एक सुलभ तथा आरामदायक विकल्प मिलेगा।

प्रदेश के 68 जनपदों में बनेंगे 'गो–संरक्षण केन्द्र'

राज्य सरकार ने प्रदेश में निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण के लिए 68 जनपदों में एक–एक वृहद गो–संरक्षण केन्द्र की स्थापना किए जाने हेतु मानकों का निर्धारण कर दिया है। शासन ने प्रत्येक गोवंश केन्द्र के लिए 120.00 लाख प्रति जनपद की दर से कुल 8160.00 लाख रूपये का प्राविधान वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया है, जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रुप में 50.00 लाख रूपये प्रति जनपद की दर से कुल 34 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी है।

केन्द्रों की स्थापना हेतु मानक निर्धारित

निर्धारित न्यूनतम मानक के अनुसार अथवा उससे बड़े मानक के वृहद गो–संरक्षण केन्द्रों की स्थापना जनपदों में की जाएगी। गो–संरक्षण केन्दों के मानक निर्धारित हैं, जिसके तहत प्रत्येक केन्द्र में अलग–अलग 4 गोवंश शेड, जिनका कुल क्षेत्रफल 14,000 वर्ग फीट हो, 2 भूसा गोदाम, (कुल क्षेत्रफल 2,000 वर्गफीट) होगा। कार्यालय/औषधि कक्ष/स्टोर–300 वर्गफीट तथा 6 कर्मचारी आवास एवं शौचालय/स्नानागार, (कुल क्षेत्रफल 1,100 वर्गफीट) होगा। चारा पानी के लिए 4 चरहियां (कुल क्षेत्रफल 800 वर्गफीट) एवं शेडो के बाहर भी खुले में कुछ चरनियां (कुल क्षेत्रफल 5,400 वर्गफीट) होगा। सबमर्सिबल पम्प/सोलर वाटर पम्प तथा दस हजार क्षमता की पानी टंकियां स्थापित की जाएंगी। बाउन्ड्रीवाल व शेडों के पृथकीकरण हेतु बाड़ की समुचित व्यवस्था होगी चाहिए। वृहद गो–संरक्षण केन्द्र का निर्माण ससमय पूर्ण कराये जाने एवं उसके अग्रेतर संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिलाधिकारी की होगी।

यू.पी.वी.सी. पाइप का क्रय ई–टेण्डर के माध्यम से किये जाने के फलस्वरूप प्रदेश के 1039 गहरी बोरिंगों के कृषकों को रू. 70 से 93 लाख तक तथा मध्यम गहरी बोरिंग के 3837 कृषकों को रू. 128 से 150 लाख तक की बचत होगी। इस प्रकार पाइप की दरों में कमी आने के कारण कृषकों को समान अनुदान पर अधिक पाइप दिया जा सकता है, अथवा बचत की धनराशि से अतिरिक्त कृषकों को लाभान्वित किया जा सकता है।

हर जनपद में किसानों को मिलेगी मध्यम एवं गहरी बोरिंग की सुविधा

लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मध्यम गहरी बोरिंगों एवं गहरी बोरिंगों के निर्माण के लिए विभिन्न विशिष्टियों के यू.पी.वी.सी. पाइप का क्रय ई–टेण्डर के माध्यम से किया गया जिसके फलस्वरूप गत वर्ष के सापेक्ष दरों में 5 प्रतिशत (मध्यम गहरी बोरिंग) से लेकर 10 प्रतिशत (गहरी बोरिंग) तक की कमी आयी है। इससे लाभार्थी कृषक को मध्यम गहरी बोरिंग कराने में प्रति बोरिंग लगभग रू. 3350–4000 तथा गहरी बोरिंग के लाभार्थी कृषक को लगभग रू. 6700–9000 तक का कम व्यय भार वहन करना पड़ेगा।

हर जनपद में उपलब्ध होंगे पाइप

इससे अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन भी होगा जो सरकार के **'कृषकों की आय दुगनी'** करने के संकल्प में एक सार्थक कदम होगा। विभाग द्वारा आपूर्ति का शेड्यूल इस प्रकार बनाया गया है कि प्रदेश के हर जनपद में हर माह पाइप की उपलब्धता बनी रहेगी। प्रदेश के सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण जनपदों सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, चित्रकूट, फतेहपुर, सोनभद्र, बलरामपुर, चन्दौली एवं बहराइच में प्राथमिकता के आधार पर पाइप की आपूर्ति की जा रही है और माह अक्टूबर तक इन जनपदों में पूरी पाइप की आपूर्ति कर दी जायेगी ताकि इनके लक्ष्यों की पूर्ति इस वर्ष के अन्त तक करके अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित की जा सके।

विभाग का प्रयास है कि इस वर्ष माह जुलाई में ही पाइप की आपूर्ति क्षेत्र में आरम्भ हो जाए जिससे कृषकों की बोरिंग समय से पूर्ण हो सकेंगी। पाइप की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आपूर्ति प्राप्त करने के उपरान्त पोस्ट इंसपेक्शन की व्यवस्था को इस वर्ष अनिवार्य किया गया है। ■

3 जुलाई 2018 को सम्पन्न प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

दो वर्ष में बनकर तैयार होगा पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे

कैबिनेट ने पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे के निर्माण की राह आसन करते हुए बैकों से 12 हजार करोड़ के ऋण लेने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह ऋण 15 वर्षो के लिए लिया जायेगा। राज्य सरकार ने शासकीय गारंटी तथा यूपीडा द्वारा ऋण चुकता न कर पाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा उस राशि को चुकाने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है।

पहले इस योजना को पूरा करने के लिए 36 माह का समय निर्धारित था, जिसे सरकार ने घटा दिया है। नई व्यवस्था के अनुसार अब अधिकतम 24 से 26 माह में इस एक्सप्रेस–वे का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

परियोजना के लिए वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने से इसे गति मिलेगी और परियोजना के माध्यम से उत्पन्न हाने वाले रोजगार संबंधी कार्यो में तेजी आएगी।

मुख्यमंत्री आवास योजना की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में

मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु जारी शासनादेश में संशोधन के उपरान्त अब ई–पेमेंट के माध्यम से संबंधित धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में अन्तरित की जाएगी। बिचौलियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने यह योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षत्रों में प्राकृतिक आपदा के कारण छत विहीन एव आश्रयहीन परिवारों, कालाबाजार से प्रभावित परिवारों, वनटांगिया तथा मुसहर वर्ग के परिवारों को आवास प्रदान करने हेतु प्रारंभ की है।

- अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद और श्रावस्ती में विकसित होंगे एयरपोर्ट
- खनिज विकास निगम की सम्पत्ति हस्तांरित होगी खनिकर्म निदेशालय को
- इलाहाबाद में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए उपयोग होगा नजूल की भूमि का

मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में यूपी बना नंबर वन

मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में कमी लाने वाले राज्यो में यूपी पहले स्थान पर है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2014–16 के सर्वे में यह निष्कर्ष उभरकर आया है कि यूपी में एमएमआर में लगभग 30 प्रतिशत की कमी आई है। देश भर में हुए इस सर्वे में 62,91,101 गर्भवती महिलाओं को सम्मिलित किया गया था। इनमें से 556 की मृत्यु हुई थी।

यूपी ने मातृ मृत्यू दर में कमी के मामले में सभी राज्यों से उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। प्रसव पूर्व देखभाल के कारण इस दर में सुधार आया है। नियमित टीकाकरण, आयरन टैबलेट, ब्लड प्रेशर तथा रक्त की जांच, एंटी नेटल चेकअप आदि के आधार पर यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सका है।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक डॉ. उज्ज्वल कुमार द्वारा प्रकाशित. सम्पादक : सुहेल वहीद अंसारी